support, if any, from the Central Government.

(v) To recommend in the light of above findings, whether any assistance is necessary and, if so, nature, extent, and duration thereof.

Computerisation of Reservation

182. SHRI RAM VILAS PASWAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to introduce computerisation of reservation on all the big stations of the country;

(b) if so, the time by which this system will be introduced; and

(c) how far it will remove the black-marketing in reservation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHAUDHURY): (a) to (c). A ststement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

A project has been taken up for computerisation of passenger seat snd berth reservations in Delhi Area. After the system is successfully established in Delhi and yields the desired benezts, similar arrangements can later on be considered for other metropolitan cities on the basis of experience gained in Delhi.

The Delhi area reservations project is likely to be completed in about two years' time.

Computerised reservation system will provide *inter alia*:

(i) instant and correct information to the passengers about availability of accommodation;

(ii) proper and correct accountal of reservation on first-come-first-served basis, eliminating any possibility of manipulations;

(iii) facilitate passengers in obtaining reservation on any train from any iounter at any location where reservation counters are provided;

(iv) reduce the time taken at the counters for making reservations and thus improve service to passenges;

(v) maintain correct accountal of fares and issue of tickets against eah reservation;

(vi) provide automatic allotment of berths to waitlisted passengers against cancellations etc.

So far as eliminating malpractices and blackmarketing in reservations is concerned, the computerised system will ensure that the system of first-come-first-served is strictly followed and there is no manipulation in this connection. It will also ensure automatic allotment of cancelled accommodation to waitlisted passengers strictly according to their turn. However, it cannot prevent black-marketing of reserved tickets by transfer of reservations which can only be prevented by physical checks.

दिल्ली परिवहन निगम को हुआ घाटा

1852. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री भीम सिंह :
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली परिवहन निगम घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान इसे कितना घाटा हुआ; और

(ग) इस घाटे को पूरा करने के लिए क्या योजना तैयार की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी, हां ।

(ख) जनवरी, 1983 तक अस्थाई रूप से 5852.23 लाख रूपये का घाटा हुआ । कार्यकरण से जो से घाटा हुआ वह भी इसमें शामिल है ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम ने बसों का अधिकाधिक प्रयोग करके, ईंधन में बचत करके, समय से मरम्मतें, कर्मचारियों से अधिकाधिक काम लेकर मालसूची पर समुचित नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करके अपनी परिचालन कुशलता बढ़ाने के लिए कदम उठाए है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 में किए गए संशोधनों के अन्तर्गत राज्य परिवहन उपक्रम अपना कर्जा ईक्विटी में दल कर अपनी ब्याज देयता को कम कर सकते हैं ।

पलामऊ और सीतापुर के बीच गाड़ियों में भारी भीड़-भाड़

1853. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या पलामऊ और सीतापुर के बीच चलने वाली गाड़ियों में भारी भीड़-भाड़ होने के कारण संसाधनों की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो संसाधन जुटाने में सरकार द्वारा हिचक दिखाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) अक्तूबर, 1982 में किए गए यातायात विश्लेषण से यह पता चला कि सीतापुर और बालामऊ के बीच इस समय चलने वाली 2 जोड़ी गाड़ियां काफी हैं । बहरहाल, जब कभी इस मार्ग पर यातायात बढ़ जाता है तब विशेष गाड़ियां चलाई जती हैं ।

भारत की सामाजिक आर्थिक परियोजनाओं के लिए "यूनिसेफ" तथा अन्य संयुक्त-राष्ट्र एजेंसियों द्वारा अनुदान में कटौती

1854. **श्री शान्तुभाई पटेल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की विभिन्न सामाजिक-आर्थिक परियोजनाओं को "यूनिसेफ" तथा अन्य संयुक्त-राष्ट्र एजेंसियां द्वारा अनुदान में अचानक कटौती किये जाने के कारण खतरा पैदा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि इन परियोजनाओं का काम चलता रहे ;

(घ) अनुसंधान कार्य से सम्बद्ध अनुदानों में कटौती के कारण कितने व्यक्ति बरोजगार हो गए ; और

(ङ) क्या उन्हें पुनः काम देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

भारत में यूनिसेफ से सहायता प्राप्त सामाजिक-आर्थिक परियोजनाएं ऐसी हैं